

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

ए०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक ५०४९-एक/२०१६ - विरुद्ध - आदेश
दिनांक ६-१२-२०१६ - पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
सागर - प्रकरण क्रमांक ३१ अ-६७/२०१५-१६

जयकुमार यादव पुत्र माखन यादव

निवासी मुहाल नं. २ सादर बाजार

सागर, तहसील एवं जिला सागर

---आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

---अनावेदक

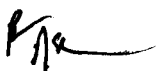
(आवेदक के अभिभाषक श्री अनिल चौबे)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री राजेश त्रिवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक १५-२-२०१७ को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण क्रमांक
३१ अ-६७/२०१५-१६ में पारित आदेश दिनांक ६-१२-२०१६ के विरुद्ध
प्रस्तुत की गई है।

२/ प्रकरण का सारंश यह है कि खनिज निरीक्षक सागर ने अनुविभागीय
अधिकारी, सागर को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक द्वारा मौजा
गढोली स्थित भूमि खसरा नंबर १०८/१ रकबा ०.०१० हैक्टर (६०० घनमीटर)
में पत्थर बोल्टर का अवैध उत्खनन किया है जिसका बाजार मूल्य
९०,०००/- रुपये है एवं इस पर अर्थदण्ड की राशि ३,६०,०००/- अधिरोपित
होती है जो की जावे। अनुविभागीय अधिकारी सागर ने प्रकरण क्रमांक ३१
अ-६७/२०१५-१६ पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को कारण बताओ नोटिस





जारी किया। आवेदक ने बचाव में लेखी उत्तर प्रस्तुत किया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी सागर ने आदेश दिनांक 6-12-2016 पारित किया तथा आवेदक पर अवैध उत्खनन करना मानकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 247 (7) के अंतर्गत 600 घनमीटर पत्थर/बोल्डर का अवैध उत्खनन मानकर 90,000/- रुपये बाजार मूल्य निर्धारित करते हुये इस राशि की चारगुणा अर्थदण्ड की राशि 3,60,000/- अधिरोपित कर वसूली के आदेश दिये। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एवं मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने तथा अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण क्रमांक 31 अ-67/2015-16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि खनिज निरीक्षक ने प्रतिवेदन दिनांक 16-2-16 प्रस्तुत कर बताया है कि आवेदक ने मौजा गढौली स्थित भूमि खसरा नंबर 108/1 रकबा 0.010 हेक्टर से (600 घनमीटर) पत्थर/बोल्डर का अवैध उत्खनन किया है जिसकी बाजार कीमत 90,000/-रु. है और इस नब्बे हजार रुपये के उत्खनन को अर्थदण्ड के रूप में चार गुणा करके तीन लाख साठ हजार रु. वसूली के आदेश दिये जाँच। कारण बताओ नोटिस दिनांक 18-2-16 जारी होने के बाद आवेदक ने लेखी उत्तर दिनांक 11-5-16 प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी को बताया है कि जब उसके द्वारा लगाये जा रहे केशर को विद्युत ही उचित दाव के कनेशन की नहीं मिली है अवैध उत्खनन का आरोप गलत है। केशर के पास जो पत्थर पड़े हैं वह सिरोजा खदान के लाये गये पत्थर हैं। खसरा नंबर 33 में खुदी डबरी छोटी तलैया है जो कृषि कार्य हेतु पानी के एकत्रीकरण के लिये खोदी गई है। आवेदक ने यह भी बताया है कि उसके द्वारा कोई अवैध उत्खनन नहीं किया है अपितु बहादुर यादव झूठी शिकायतें कर रहा है।

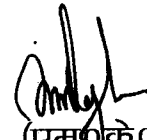
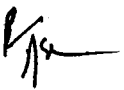
शिकायतकर्ता बहादुर सिंह यादव के आवेदन में वर्णित तथ्य एवं आवेदक द्वारा कारण बताओ नोटिस के बचाव में प्रस्तुत लेखी उत्तर के तथ्यों के सम्बंध में अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण क्रमांक 31 अ-67/ 2015-16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों



का न तो पुष्टिकरण कराया है और न ही स्वयं स्थल निरीक्षण किया है। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 6-12-16 खनिज निरीक्षक सागर के प्रतिवेदन पर से पारित किया गया है जिसके कारण ऐसा आदेश दूषित प्रक्रिया पर आधारित है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी सागर ने शासन पक्ष की साक्ष्य अंकित की है। साक्षी पंचू पुत्र चेतु अहिरवार ने बताया है कि खनिज निरीक्षक एवं पटवारी मौके पर गये थे। मेरे पंचनामा पर हस्ताक्षर कराये थे। अवैध उत्खनन फोर लाइन के कर्मचारियों द्वारा किया गया है जयकुमार द्वारा नहीं किया गया। हलका पटवारी नितिन यादव ने कथनों में उत्खनन के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया है। स्पष्ट है कि शासन पक्ष की साक्ष्य के कथनों से यह प्रमाणित नहीं हो सका है कि आवेदक ने ही उपरोक्त आये तथ्यों अनुसार पत्थर/बोल्डर अवैध उत्खनन किया है इसके विपरीत आवेदक यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि फोर लेन निर्माण के समय निर्माण वालों ने खुदाई की है। इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के विरुद्ध अवैध उत्खनन करना मानकर उस पर 90000/- रु. का अवैध उत्खनन करना तथा चौगुणी राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित करना न्याय की श्रेणी में नहीं माना जा सकता, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 31 अ-67/15-16 में पारित आदेश दिनांक 6-12-2016 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 31 अ-67/15-16 में पारित आदेश दिनांक 6-12-2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाती है।



(एम0के0सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर